

मानक शर्त मात्य होने का प्रभाण पत्र

- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
 - प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल काश्ठित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
 - याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 - भूमि का स्वयं निरोक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
 - हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निश्चारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा। जिससे यापक विभाग सहमत है।
 - भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
 - हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारीयों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - बहसफूल्य वन सम्पदा से आचारित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा कि क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छ विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
 - सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध आदि की भी देखभाल करेगा।
 - याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः विभाग के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग का वापस हो जायेगा।
 - सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर सरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांतीनियों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सांतीनियों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 60830 दिनांक 10.02.82 में निहित आदाशों का पालन भी सांतीनियों द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्ग को फेर बदल कर पवका करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
 - वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकंतित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
 - वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे होता है तो सक्ते और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्बन्ध न हो सके तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
 - हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के सम्पुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा वन सम्पुल्य गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो वी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मी० एवं 30 डिग्री से अधिक डाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी निषिद्ध है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संस्करण स्तर पर ही होगा।
 - वन भूमि के उपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को उंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम ऐडो की संख्या संयुक्त झल निरीक्षण करके सम्बन्धित वन संरक्षक वन निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
 - यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की समानता होती है और नहर की दोनों पटाटियों को पवका करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
 - उपरलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
 - वन भूमि की वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुदायित स्तर से प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई शर्त याचक विभाग को मान्य है।